

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग - 1
देहरादून : दिनांक : 01 अगस्त, 2023

कार्यालय ज्ञाप

वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 474/02(150)/XXVII(1)/2019 दिनांक 01 अगस्त, 2019 के द्वारा शासन स्तर पर विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं आदि की स्वीकृति हेतु व्यय वित्त समिति के गठन, कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2- तत्क्रम में योजनाओं की स्वीकृति की प्रक्रिया में गतिशीलता लाए जाने एवं समय से साथ परिवर्तनीय बाजार दरों को संज्ञान में रखते हुए व्यय वित्त समिति के कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रक्रिया में परिवर्तन किए जाने हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 01 अगस्त, 2019 के कतिपय प्रस्तरों को तत्काल प्रभाव से निम्नवत संशोधित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : -

कार्यालय ज्ञाप दिनांक 01.8. 2019 का प्रस्तर संख्या	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
2A	समिति के सम्मुख ऐसी समस्त योजनायें/परियोजनायें, जिसमें समस्त व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना हो अथवा उस प्रस्ताव में कोई अंश, जिनमें किसी एक इकाई पर रु 50.00 लाख का वार्षिक आवर्तक व्यय अथवा रु 5.00 करोड़ या उससे अधिक का अनावर्तक व्यय निहित हो, तो ऐसे प्रस्ताव अनिवार्यतः व्यय वित्त समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे।	राज्य सरकार द्वारा व्ययभार वहन किये जाने वाली ऐसी समस्त योजनायें/परियोजनायें, जिनमें किसी एक इकाई पर रु 1.00 करोड़ या उससे अधिक का वार्षिक आवर्तक व्यय अथवा रु 10.00 करोड़ से अधिक का अनावर्तक व्यय निहित हो, तो ऐसे प्रस्ताव अनिवार्यतः व्यय वित्त समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे।
2C	CSS के अन्तर्गत कोई योजना जो पूर्व से चल रही हो (On Going Scheme) सामान्यतः व्यय वित्त समिति की परिधि से आच्छादित नहीं होंगी। परन्तु इस प्रकार की योजना का ऐसा घटक जो नई परियोजना हो एवं उस पर रु 50.00 लाख का वार्षिक आवर्तक व्यय अथवा रु 5.00 करोड़ या उससे अधिक का अनावर्तक व्यय निहित हो, तो ऐसे प्रस्ताव व्यय वित्त समिति की परिधि से आच्छादित होंगे। (उदाहरण-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत पूर्व से चल रही (On	CSS के अन्तर्गत कोई योजना जो पूर्व से चल रही हो (On Going Scheme) सामान्यतः व्यय वित्त समिति की परिधि से आच्छादित नहीं होंगी। परन्तु इस प्रकार की योजना का ऐसा घटक, जो नई परियोजना हो एवं उस पर रु 1.00 करोड़ या उससे अधिक का वार्षिक आवर्तक व्यय अथवा रु 10.00 करोड़ से अधिक का अनावर्तक व्यय निहित हो, तो ऐसे प्रस्ताव व्यय वित्त समिति की परिधि से आच्छादित होंगे। (उदाहरण-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत पूर्व से चल रही (On Scheme) NHM स्कीम सामान्यतः व्यय

1

	<p>अंतर्गत राज्य योजना आयोग के तकनीकी अभियंताओं को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जायेगा और विभागीय समिति द्वारा उनके सुझावों का संज्ञान लेते हुए बैठक का कार्यवृत्त निर्गत किया जायेगा। विभागीय समिति के समक्ष 'परिशिष्ट-क' के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा।</p>
<p>4(4)</p>	<p>प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्तुत रु 1.00 करोड़ से अधिक के आगणनों का तकनीकी परीक्षण पूर्व की भांति तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ (TAC) द्वारा किया जायेगा। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं०-156 दिनांक 24.02.2015 एवं शासनादेश सं०-359, दिनांक 23.03.2015 में दी गयी व्यवस्था पूर्ववत् रहेगी। इनमें से रु 5.00 करोड़ अथवा इससे अधिक के आगणनों का तकनीकी परीक्षण तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ (TAC) से किये जाने के उपरान्त प्रस्ताव का परीक्षण व्यय वित्त समिति द्वारा किया जायेगा।</p>

3- उक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 01 अगस्त, 2019 को मात्र उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

Signed by Dilip Jawalkar

Signed by Dilip Jawalkar

Date: 31-05-2023 10:55:47

(दिलीप जावलकर)

सचिव ।

संख्या : 12603(1)/XXVII (1)/2023 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
- 2- निजी सचिव, मा. वित्त मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
- 3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
- 6- महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड।

- 7- आयुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
- 8- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 9- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- 10- मंत्रिपरिषद् अंगुभाग, उत्तराखण्ड शासन को मा. मंत्रिमण्डल के आदेशों के क्रियान्वयन संबंधी उनके पत्र संख्या 4/2/IX/XXI/2023-CX दिनांक 19 मई, 2023 के क्रम में।
- 11- राज्य योजना आयोग/नोडल विभाग।
- 12- गार्ड फाइल।

(दिलीप जावलकर)
सचिव।